International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
e-ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 01(II), January - March, 2026, pp. 196-199

रीवा जिले में रोजगार सृजन पर सरकारी योजनाओं का आर्थिक प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुमन शर्मा[1] | डॉ. विद्युत प्रकाश मिश्रा[2*]

[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)।
[2]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.)।

[*]Corresponding Author: byadwalsimi123@gmail.com

Citation: शर्मा, सुमन एवं मिश्रा, विद्युत (2026). रीवा जिले में रोजगार सृजन पर सरकारी योजनाओं का आर्थिक प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(01(II)), 196–199. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.1(II).8778

सार

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में रोजगार सृजन आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता तथा समावेशी प्रगति का एक मूलभूत आधार है। बदलते आर्थिक परिदृश्य में सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है, जिनका उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या का शमन करना, आय स्तर में वृद्धि करना तथा ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। प्रस्तुत शोध–पत्र में रीवा जिले के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि शासकीय योजनाओं के प्रभाव से लाभार्थियों की आय में वृद्धि, उपभोग क्षमता में विस्तार तथा जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। साथ ही, स्थानीय बाजार संरचना एवं लघु आर्थिक गतिविधियों में भी सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का संकेत देते हैं। तथापि, अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का अभाव, लाभार्थियों में सीमित जागरूकता तथा प्रशासनिक जटिलताएँ अभी भी प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि योजनाओं के प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन हेतु सुदृढ़ निगरानी तंत्र विकसित किया जाए तथा लक्षित वर्ग को योजनाओं के प्रति अधिक जागरूक एवं सक्षम बनाया जाए, जिससे इन योजनाओं के आर्थिक लाभों का अधिकतम प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

शब्दकोश: *रोजगार सृजन, शासकीय योजनाएँ, आर्थिक प्रभाव, क्षेत्रीय विकास, आय स्तर, उपभोग क्षमता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी।*

प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन एक प्रमुख चुनौती एवं अवसर दोनों के रूप में उभरकर सामने आया है। बढ़ती जनसंख्या, सीमित संसाधन एवं औद्योगिक विकास की असमान गति के कारण बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है, जिनका उद्देश्य न केवल रोजगार के अवसरों का सृजन करना है, बल्कि आर्थिक विकास को

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

समावेशी एवं संतुलित बनाना भी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण सरकार ने विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों के लिए योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जैसे– मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाएँ आदि। इन योजनाओं के माध्यम से श्रम–प्रधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

मध्यप्रदेश का रीवा जिला सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ कृषि एवं लघु उद्योग प्रमुख आजीविका के साधन हैं। इस क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का प्रभाव रोजगार सृजन, आय वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। तथापि, योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे– सूचना का अभाव, प्रशासनिक जटिलताएँ एवं संसाधनों का असमान वितरण। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो रोजगार सृजन केवल सामाजिक कल्याण का विषय नहीं है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, बाजार संरचना के विकास एवं उपभोग स्तर में वृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। रोजगार बढ़ने से आय में वृद्धि होती है, जिससे उपभोग एवं निवेश दोनों में वृद्धि होती है, जो अंततः आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य रीवा जिले में सरकारी योजनाओं के माध्यम से उत्पन्न रोजगार के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि योजनाओं के माध्यम से प्राप्त रोजगार ने लोगों के जीवन स्तर, आय, बचत एवं निवेश पर क्या प्रभाव डाला है। साथ ही यह अध्ययन यह भी जांचता है कि योजनाओं का लाभ किस सीमा तक लक्षित वर्ग तक पहुँच पा रहा है। अतः यह अध्ययन न केवल सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, बल्कि यह भी सुझाव प्रदान करता है कि किस प्रकार इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है ताकि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिल सके।

शोध के उद्देश्य

रोजगार सृजन किसी भी अर्थव्यवस्था के सतत् विकास का आधार होता है। विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना न केवल सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करता है। रीवा जिले में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन की प्रक्रिया का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि इनके वास्तविक आर्थिक प्रभाव को समझा जा सके। प्रस्तुत शोध कार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित प्रस्तुत हैं, जो इस प्रकार है –

- सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन की स्थिति एवं उसके आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना।
- योजनाओं के कारण आय, उपभोग एवं बचत स्तर में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं सुधार की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े रीवा जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से चयनित 300 उत्तरदाताओं से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से संकलित किए गए हैं। इन उत्तरदाताओं में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, बेरोजगार युवा एवं स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं। द्वितीयक आंकड़े विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षण, पत्र–पत्रिकाओं एवं शोध आलेखों से प्राप्त किए गए हैं। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विधि एवं तुलनात्मक विश्लेषण तकनीकों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार यह शोध प्राथमिक अनुभवजन्य तथ्यों एवं द्वितीयक स्रोतों के आधार पर सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

विश्लेषण

रीवा जिले में सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि उन्हें योजनाओं के माध्यम से अस्थायी अथवा स्थायी रोजगार प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि रोजगार प्राप्त होने के पश्चात उत्तरदाताओं की उपभोग क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय बाजार में मांग बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार हुआ है, जो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से सकारात्मक संकेत है। इस प्रकार कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त रोजगार स्थायी नहीं है तथा आय का स्तर भी अपेक्षाकृत कम है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के लाभ के वितरण में असमानता एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि जिन क्षेत्रों में जागरूकता अधिक है, वहाँ योजनाओं का प्रभाव अधिक सकारात्मक रहा है। वहीं, कम जागरूकता वाले क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ सीमित रहा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव है, किन्तु इसके प्रभाव को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। अतः अध्ययन क्षेत्र में सरकारी योजना से प्राप्त रोजगार का प्रभाव से संबंधित विवरण तालिका क्रमांक–01 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका 1: सरकारी योजनाओं से प्राप्त रोजगार का प्रभाव संबंधी विवरण

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
1.	आय में वृद्धि	120	40%
2.	रोजगार में स्थिरता	60	20%
3.	जीवन स्तर में सुधार	75	25%
4.	कोई विशेष प्रभाव नहीं	45	15%
कुल योग		300	100%

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

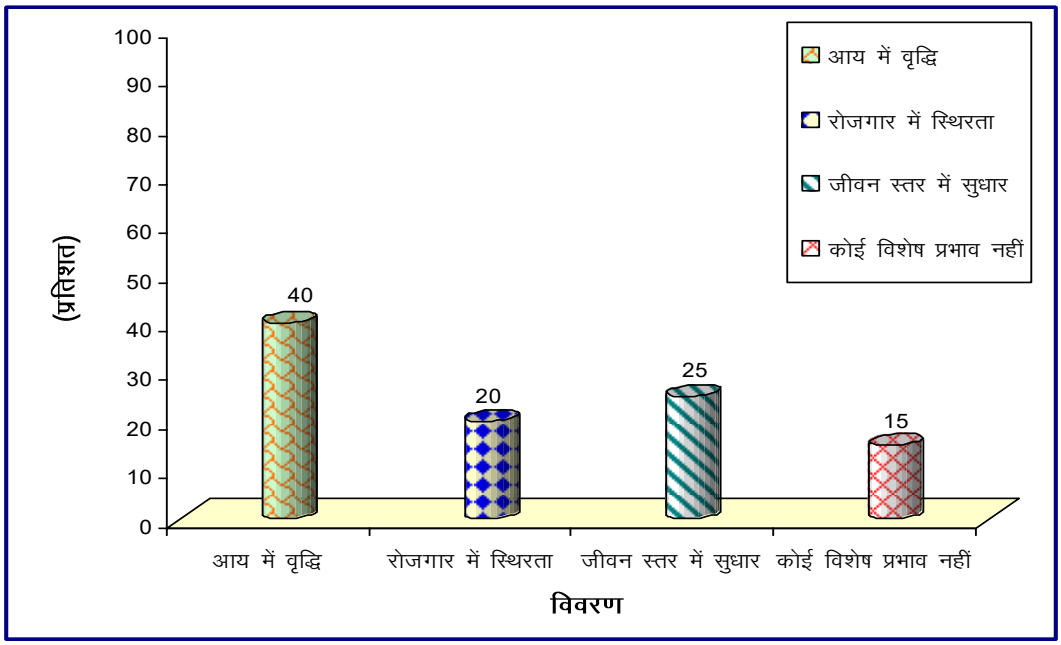

आरेख 1: सरकारी योजनाओं से प्राप्त रोजगार का प्रभाव संबंधी विवरण

उपरोक्त तालिका एवं आरेख के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में से 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि योजनाएँ आर्थिक दृष्टि से प्रभावी रही हैं। 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जीवन स्तर में सुधार की बात कही, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रोजगार सृजन का प्रभाव केवल आय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रोजगार की स्थिरता को एक प्रमुख मुद्दा बताया, जो यह संकेत देता है कि योजनाओं में दीर्घकालिक रोजगार सृजन की आवश्यकता है। इसी क्रम में 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई विशेष प्रभाव न होने की बात कही, जो योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी एवं जागरूकता के अभाव को दर्शाता है।

शोध की समस्याएँ एवं सुझाव

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि रोजगार योजनाओं के प्रभाव का आकलन करते समय डेटा की सटीकता एक प्रमुख समस्या है। कई उत्तरदाता योजनाओं से प्राप्त लाभ के बारे में स्पष्ट जानकारी देने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त योजनाओं का असमान क्रियान्वयन एवं संसाधनों का असंतुलित वितरण भी अध्ययन में बाधा उत्पन्न करता है। सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पारदर्शिता एवं निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए। साथ ही, लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि रीवा जिले में सरकारी योजनाओं ने रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि रोजगार सृजन के कारण उपभोग एवं निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय बाजार एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। इस प्रकार योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ कमियाँ भी पाई गई हैं, जैसे– अस्थायी रोजगार, जागरूकता का अभाव एवं संसाधनों का असमान वितरण। अतः यह आवश्यक है कि इन कमियों को दूर कर योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आर.के., भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली, 2019
2. गुप्ता, एस.पी., रोजगार एवं विकास, जयपुर, 2020
3. Government of India, Economic Survey] 2021
4. RBI Report, Annual Publication] 2022
5. सिंह, वी., ग्रामीण विकास अध्ययन, 2018
6. Yojana Magazine, 2023
7. Kurukshetra Magazine, 2022.

❑❑❑